

**The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE**

**Monday, 23 Sep, 2024**

**Edition: International Table of Contents**

<b>Page 01</b> <b>Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध</b>	क्वाड मीट ने समुद्री और स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की
<b>Page 06</b> <b>Syllabus : प्रारंभिक तथ्य</b>	दलितों पर अत्याचार के मामलों में यूपी, राजस्थान, MP सबसे आगे: रिपोर्ट
<b>Page 10</b> <b>Syllabus : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था</b>	GDP का अनुमान लगाने में आने वाली खामियाँ
<b>Page 11</b> <b>Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति</b>	न्यायिक नियुक्तियाँ और निराशाएँ
<b>टेम्पल इन न्यूज़</b>	तिरुपति बालाजी मंदिर
<b>Page 08 : संपादकीय विश्लेषण:</b> <b>Syllabus : GS 2 : शासन – सरकारी नीतियाँ</b>	भारत को एक 'राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति' की आवश्यकता है

**Page 01 : GS 2 : International Relations – Regional and global groupings**

सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड देशों के नेता अपने छठे शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए।

- ➔ बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटना भी था, जिसमें इंडो-पैसिफिक में समुद्री आक्रामकता और यूक्रेन में चल रहे युद्ध शामिल हैं।
- ➔ उन्होंने आपसी समर्थन और सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की।

## Quad meet launches maritime and health initiatives

**Sriram Lakshman**  
WILMINGTON (DELAWARE)

Leaders of the Quad group of countries – Prime Minister Narendra Modi, U.S. President Joe Biden, Australian Prime Minister Anthony Albanese and Japanese Prime Minister Fumio Kishida – met at their sixth summit-level meeting at Archmere Academy, Mr. Biden's former school in Claymont, Delaware, to announce a broad range of outcomes. These included the launch of a new coast guard exercise, a logistics network, expansion of maritime surveillance, and a project to combat cervical cancer.

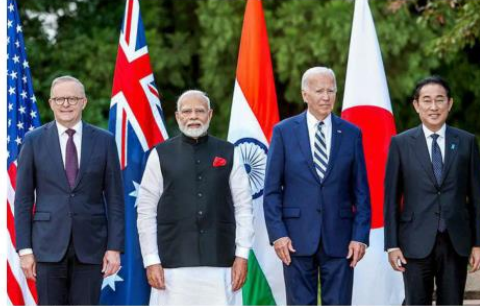
In terms of positions, the Quad strongly condemned aggression in the East and South China Sea and expressed alarm over the war in Ukraine, noting that all four leaders had vi-

sited the country.

The 'Quad Cancer Moonshot' will involve contributions from all four countries to combat cervical cancer. India will commit \$10 million towards screening for the disease. Vaccine manufacturer Serum Institute of India and Gavi will provide up to 40 million vaccines for the region, "subject to approvals".

The countries announced the Quad-at-Sea Ship Observer Mission in 2025 to improve interoperability and maritime safety. Future coast guard missions are planned for after 2025. A logistics network pilot project was also launched, which will involve Quad countries sharing airlift capacity to support disaster response.

A Maritime Initiative for Training in the Indo-Pacific (MAITRI) to train Quad



(From left) Anthony Albanese, Narendra Modi, Joe Biden, and Fumio Kishida at the 'Cancer Moonshot' event in Delaware. ANI

partners "to monitor and secure their waters, enforce their laws, and deter unlawful behaviour" was also announced. India will host the first MAITRI workshop in 2025.

A maritime legal dialogue has been launched to support actions to uphold the rules-based order, the statement said.

Quad members con-

demned maritime aggression, with pointed references to situations involving China, which is currently embroiled in tensions with the Philippines, most recently over the latter's coast guard presence on the Sabina shoal, 150 km off its west coast.

"We are seriously concerned about the situation in the East and South Chi-

na Seas," they said, as they expressed concern about the militarisation of disputed features and intimidation in the South China Sea.

The statement condemns the dangerous use of coast guard and maritime militia vessels and opposes the disruption of other countries' offshore resource exploitation activities.

### War in Ukraine

While there was no direct mention of Russia, presumably out of consideration for India, which shares a close relationship with Moscow, the joint statement had references that have been associated with a condemnation of Russia's invasion of Ukraine, such as Quad countries offering their "unwavering" support for the United Nations Charter. The countries ex-

pressed their "deepest concern" for the war in Ukraine and its consequences.

"Each of us has visited Ukraine since the war began and seen this firsthand; we reiterate the need for a comprehensive, just, and lasting peace in line with international law, consistent with the purposes and principles of the UN Charter, including respect for sovereignty and territorial integrity," the statement says. It also notes the impact the war has had on food and energy security, especially for developing countries.

The Quad fellowship, to promote STEM education, has been expanded to include 50 scholarships worth \$5,00,000 for students from the region to study at government-funded technical institutions in India.

### समाचारों का विश्लेषण:

#### ➔ क्वाड क्या है?

- चार लोकतंत्रों - भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान- के समूह को चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड के रूप में जाना जाता है।
- इस समूह का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक में कानून के शासन के आधार पर एक स्वतंत्र और खुली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

### उद्देश्य: समूह के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं

#### ○ समुद्री सुरक्षा,

- कोविड-19 संकट का मुकाबला करना, विशेष रूप से वैक्सीन कूटनीति के संदर्भ में,
- जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को संबोधित करना,
- क्षेत्र में निवेश के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और
- तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना।

### क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले

- ➔ नया तटरक्षक अभ्यास: 2025 में क्राड-एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरूआत का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच अंतर-संचालन और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है।
- ➔ इंडो-पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल (MAITRI): क्राड भागीदारों को उनके जल की निगरानी और सुरक्षा में सहायता करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें भारत 2025 में उद्घाटन कार्यशाला की मेजबानी करने वाला है।
- ➔ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट: क्राड देश आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एयरलिफ्ट क्षमता साझा करेंगे।
- ➔ सर्वाइकल कैसर से मुकाबला: 'क्राड कैसर मूनशॉट' पहल में सर्वाइकल कैसर की जांच के लिए भारत की ओर से 10 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता शामिल होगी, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और गावी इस क्षेत्र के लिए 40 मिलियन तक टीके उपलब्ध कराएंगे।
- ➔ समुद्री कानूनी संवाद: समुद्री मुद्दों में नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से कार्रवाई का समर्थन करने के लिए एक संवाद शुरू किया गया है।
- ➔ समुद्री आक्रामकता की निंदा: क्राड नेताओं ने पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में समुद्री आक्रामकता पर गहरी चिंता व्यक्त की, सैन्यीकरण और धमकी के मुद्दों पर प्रकाश डाला।
- ➔ यूक्रेन और गाजा संघर्ष: घोषणापत्र में यूक्रेन युद्ध के वैश्विक प्रभाव, विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर, को छुआ गया और गाजा को मानवीय सहायता बढ़ाने का आह्वान किया गया।
- ➔ क्राड फेलोशिप विस्तार: STEM शिक्षा के लिए फेलोशिप का विस्तार किया गया है, जिसमें भारत में सरकारी वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में अध्ययन करने के लिए क्षेत्र के छात्रों के लिए \$500,000 मूल्य की 50 छात्रवृत्तियाँ शामिल हैं।

### भारत के लिए क्राड का महत्व

#### ➔ चीन के आर्थिक और सैन्य उदय का मुकाबला करना

- क्राड के सदस्य के रूप में, अपनी सीमाओं पर चीनी शत्रुता में वृद्धि की स्थिति में, भारत इसका मुकाबला करने के लिए अन्य क्राड देशों का समर्थन ले सकता है।
- इसके अलावा, भारत अपने नौसैनिक मोर्चे की मदद भी ले सकता है और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक अन्वेषण कर सकता है।

#### ➔ स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के लिए

- शिखर सम्मेलन में एक ऐसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रयास करने की शपथ ली गई, जो स्वतंत्र, खुला, समावेशी और दबाव से मुक्त हो।
- रणनीतिक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता और दबावपूर्ण प्रकृति के मद्देनजर भारत के लिए यह पहलू महत्वपूर्ण हो जाता है।

#### ➔ भारत एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में

- भारत को एक क्षेत्र के रूप में इस भूमिका को निभाने के लिए, हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को बनाए रखने और बनाए रखने की आवश्यकता है।
- इस परिप्रेक्ष्य में, QUAD भारत को क्षेत्र में साझेदारी के माध्यम से सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

#### ➔ बहुध्रुवीय विश्व

- भारत ने एक नियम आधारित बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन किया है और QUAD क्षेत्रीय महाशक्ति बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में इसकी मदद कर सकता है।

➔ **कोविड के बाद की कूटनीति**

- महामारी के कारण दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आया है, और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता हो सकती है।
- ऐसी स्थिति में, भारत को विनिर्माण क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए आधार स्थापित करने के लिए QUAD समूह के साथ अपनी कूटनीति का उपयोग करना चाहिए।

**UPSC Mains PYQ: 2020**

**प्रश्न: 'चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड)' वर्तमान समय में एक सैन्य गठबंधन से एक व्यापारिक ब्लॉक में तब्दील हो रहा है – चर्चा करें।**





हाल ही में आई एक रिपोर्ट में भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों की एक महत्वपूर्ण सांद्रता का खुलासा किया गया है, खासकर 13 राज्यों में।

➔ इसमें दोषसिद्धि दरों में गिरावट को रेखांकित किया गया है और कमजोर समुदायों की सुरक्षा के लिए लक्षित हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

# U.P., Rajasthan, M.P. top in cases of atrocities on Dalits: report

Of the 51,656 cases registered under the law for SCs in 2022, Uttar Pradesh accounts for 23.78%, followed by Rajasthan, 16.75%, and Madhya Pradesh, 14.97%. Similarly, of the 9,735 cases filed for STs, Madhya Pradesh reports the highest 30.61%

Press Trust of India  
NEW DELHI

Nearly 97.7% of all cases of atrocities against Scheduled Castes in 2022 were reported from 13 States, with Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh recording the highest number of such crimes, according to a new government report.

According to the latest report under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act by the Social Justice and Empowerment Ministry, the majority of atrocities against Scheduled Tribes (STs) were also concentrated in 13 states, which reported 98.91% of all cases in 2022.

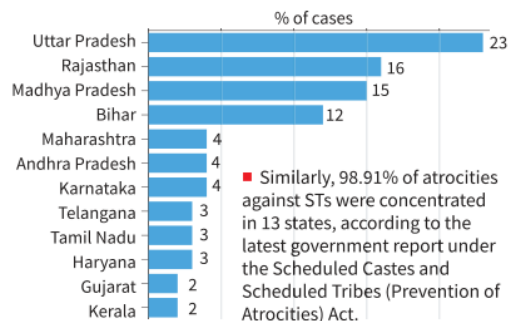
Of the 51,656 cases registered under the law for Scheduled Castes (SCs) in 2022, Uttar Pradesh accounted for 23.78% of the total cases with 12,287, followed by Rajasthan with 8,651 (16.75%) and Madhya Pradesh with 7,732 (14.97%). Other States with a significant number of cases of atrocities against SCs were Bihar with 6,799 (13.16%), Odisha with 3,576 (6.93%), and Maharashtra

## Atrocities on Dalits, tribal people

The chart shows the States accounting for 97.7% of total cases of atrocities against members of Scheduled Castes during the year 2022.



Source: Ministry of Social Justice and Empowerment



Similarly, 98.91% of atrocities against STs were concentrated in 13 states, according to the latest government report under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act.

with 2,706 (5.24%). These six States accounted for nearly 81% of the cases.

“Thirteen states, cumulatively accounting for 97.7% (51,656) of the total cases (52,866) relating to offences of atrocities against members of SCs, registered under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, in conjunction with the Indian Penal Code, during the year 2022,” the report said.

Similarly, the majority of cases of atrocities against STs were concentrated in 13 states. Of the 9,735 cases registered under the law for STs, Mad-

hya Pradesh reported the highest number at 2,979 (30.61%), the report said.

Rajasthan had the second highest number of cases at 2,498 (25.66%) while Odisha recorded 773 (7.94%). Other States with a significant number of cases included Maharashtra with 691 (7.10%) and Andhra Pradesh with 499 (5.13%). The data also provided insight into the status of investigations and charge-sheeting under the Act.

Among the SC-related cases, 60.38% led to chargesheets being filed while 14.78% were concluded with final reports due to reasons such as false

claims or lack of evidence. By the end of 2022, investigation was pending in 17,166 cases.

For ST-related cases, 63.32% resulted in charge sheets being filed while 14.71% ended with final reports. At the end of the period under review, 2,702 cases involving atrocities against STs were still under investigation.

One of the most concerning trends highlighted in the report is the declining conviction rate for cases under the Act. In 2022, the conviction rate dropped to 32.4% from 39.2% in 2020. Moreover, of 498 districts in 14 States,

only 194 had established special courts to expedite trials in these cases.

The report also identified specific districts particularly prone to atrocities with only 10 States and Union Territories declaring such districts. It emphasised the need for targeted interventions in these districts to curb the caste-based violence and ensure stronger protection for vulnerable communities.

SC/ST protection cells had been set up in Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, NCT of Delhi, Jammu and Kashmir, Ladakh and Puducherry, according to the report.

Special police stations for registration of complaints of offences against SCs and STs have been set up by Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Kerala and Madhya Pradesh.

### समाचार का विश्लेषण:

- वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों (SC) के विरुद्ध दर्ज अत्याचारों में से 97.7% मामले 13 राज्यों में हुए, जिनमें से उत्तर प्रदेश में कुल मामलों का 23.78% हिस्सा था।
- अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार से संबंधित कुल 51,656 मामले दर्ज किए गए।
- मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों (ST) के विरुद्ध अत्याचारों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, जहाँ 30.61% मामले दर्ज किए गए।
- एससी/एसटी मामलों में दोषसिद्धि दर वर्ष 2022 में घटकर 32.4% रह गई।
- मुकदमों में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतें 498 जिलों में से केवल 194 में मौजूद हैं।
- कई राज्यों ने इन समुदायों के विरुद्ध अत्याचारों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एससी/एसटी सुरक्षा प्रकोष्ठ और विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं।

### UPSC Prelims PYQ : 2019

**प्रश्न:** भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि का निजी पक्षों को हस्तांतरण शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है?

- (a) तीसरी अनुसूची
- (b) पांचवीं अनुसूची
- (c) नौवीं अनुसूची
- (d) बारहवीं अनुसूची

**उत्तर: (b)**

Page 10: GS 3 : Indian Economy

लेख में भारत की जीडीपी श्रृंखला के आगामी संशोधन पर चर्चा की गई है, जिसमें मूल्य संवर्धन का अनुमान लगाने के लिए जीएसटी डेटा के उपयोग पर विचार करते हुए 2020-21 को नए आधार वर्ष के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

➔ यह जीडीपी अनुमानों की अखंडता और नए डेटासेट के सत्यापन की आवश्यकता के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डालता है।

# On the pitfalls of estimating GDP

The ongoing GDP series is due for revision. The official agency is considering using GST data to estimate value addition. However, the agency should be careful to not apply unverified datasets and shaky methodologies without adequate testing and validations for GDP estimation

**ECONOMIC NOTES**

R. Nagaraj

**G**ross Domestic Product, or GDP, is the most significant measure of a country's economic size. It is also a universal denominator for comparing indicators across countries and regions or for sizing up tax burdens or welfare expenditures. GDP is usually more meaningful at "constant" prices or in "real" terms – netting out the effect of price changes. The real GDP is estimated for the "base year", requiring a variety of datasets on output, prices, and employment. Every 5-10 years, the GDP base year is revised to account for changes in relative prices and output composition. The National Statistical Office (NSO) is tasked with "revising" the GDP series, usually drawing upon expertise from many fields.

The ongoing GDP series with the base year 2011-12 is due for revision. 2020-21 is the proposed new base year. All required major datasets are said to be available except for Census data. The NSO is considering using the goods and services tax (GST) data to estimate value addition, replacing the currently used Ministry of Corporate Affairs' MCA-21 database for the Private Corporate Sector (PCS), which accounts for about 38% of GDP.

**Why the change?**

After all, the MCA-21 database was brought in only in the last revision, with 2011-12 as the base year. Previous to that, the Annual Survey of Industries (ASI) was the long-standing workhorse for estimating factory manufacturing value-added. The Reserve Bank of India's (RBI) small sample of large companies, with the majority paid-up capital of PCS, was used to estimate the non-financial corporate sector output. The statistical agency changed it to the MCA-21 database as the ASI claimed to miss out on value addition outside of factory premises in a corporate entity. Likewise, reportedly, the



GETTY IMAGES

RBI sample was inadequate to account for the rapidly growing PCS. Moreover, the availability of the extensive and up-to-date MCA-21 data, obtained from the mandatory filing of corporate annual returns and quarterly corporate results – it was contended – would enable fuller capturing of the corporate output.

The 2011-12 base year GDP (replacing the 2004-05 base year series) showed a marginally smaller absolute GDP size and a faster growth rate. But for the manufacturing sector in 2013-14 at constant prices, the annual growth rate was (+) 5.4% in the new series, compared to (-) 1.90% in the earlier series. Such a sharp divergence in the rate and direction of industrial growth by the two GDP series was a surprise. Moreover, the upward revision of the industrial growth rate didn't square with related macro aggregates, such as bank credit growth or industrial capacity utilisation, leading to

widespread scepticism of the new GDP estimates. Statistical investigations zeroed in on an untested or inadequately vetted MCA database as the source of the overestimation problem.

The official agency, however, defended its new estimates, claiming they capture value addition more completely, using a much more extensive database, improved estimation methods, and following the latest template of international best practices. Critics, however, wondered if a bigger dataset is necessarily a better data set. And if the new estimates were better or overestimates. The statistical dispute remained unresolved as the government refused to make the MCA data available for independent scrutiny or reveal its estimation methodology for verification.

**Systematic overestimation**

With time, however, it has been possible to compare estimates of Gross Value

Added (GVA) in the manufacturing sector as per GDP series (in the National Accounts Statistics) and by the ASI – based on production accounts of registered factories – for a reasonably long period. We compared (i) GVA and (ii) Gross Fixed Capital Formation (GFCF) (fixed investment) at constant prices for 2012-13 to 2019-20 as reported by the NAS and ASI. The results were startling. The average annual growth rate of GVA in NAS was 6.2%, while it was only 3.2% in ASI. The difference was much sharper in GFCF: 4.5% by NAS and 0.3% by ASI, respectively. These comparisons show a systematic overestimation in NAS estimates (based on the MCA-21 database) compared to the ASI-based estimates, vindicating the doubts raised about the integrity of the GDP estimates.

The evidence presented here is a cautionary tale for the proposed use of GST data for GDP estimation. It's a stark reminder of the need for the official agency to guard against the hasty application of unverified datasets and shaky methodologies without adequate testing and validations for GDP estimation. NSO must initiate pilot studies to verify the GST dataset's suitability for value addition estimation of specific industries, sectors, and States. Such validation is crucial to ensure the estimation's truthfulness and instill confidence in the integrity of the GST data. Alternatively, NSO could explore reverting to ASI to estimate GDP manufacturing, as the database is now available with a shorter time lag.

GST data can be a game-changer for GDP estimation in the proposed revision. It is a large and up-to-date database, however, its details are in a black box, as it has not been open for policy research. Without systematic analyses and cross-validation disaggregated by production and institutional sectors and regions by independent agencies, the validity of GDP estimates on GST data will be hard to establish.

R. Nagaraj is with the Centre for Liberal Education, IIT Bombay.

**THE GIST**

➔ Gross Domestic Product, or GDP, is the most significant measure of a country's economic size. It is also a universal denominator for comparing indicators across countries and regions or for sizing up tax burdens or welfare expenditures.

➔ For the manufacturing sector in 2013-14 at constant prices, the annual growth rate was (+) 5.4% in the new series, compared to (-) 1.90% in the earlier series. Such a sharp divergence in the rate and direction of industrial growth by the two GDP series was a surprise.

➔ The evidence presented here is a cautionary tale for the proposed use of GST data for GDP estimation.

**जीडीपी का महत्व**

- ➔ सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी देश के आर्थिक आकार का एक महत्वपूर्ण माप है और विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक संकेतकों की तुलना करने के लिए एक सार्वभौमिक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।
- ➔ मूल्य परिवर्तनों के लिए समायोजित वास्तविक जीडीपी को अक्सर सटीक आर्थिक आकलन के लिए प्राथमिकता दी जाती है। इसकी गणना आउटपुट, कीमतों और रोजगार से संबंधित डेटासेट के आधार पर की जाती है।



### आधार वर्ष संशोधन

- 2011-12 के आधार वर्ष वाली वर्तमान जीडीपी श्रृंखला में संशोधन होना है, जिसमें 2020-21 को नए आधार वर्ष के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
- इस संशोधन के लिए मुख्य डेटासेट अधिकांशतः उपलब्ध हैं, जनगणना डेटा को छोड़कर।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) मूल्य संवर्धन का अनुमान लगाने के लिए माल और सेवा कर (GST) डेटा का उपयोग करने की योजना बना रहा है, जो निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र (PSC) के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA-21) के पिछले डेटाबेस की जगह लेगा।

### परिवर्तन का औचित्य

- MCA-21 डेटाबेस को 2011-12 आधार वर्ष के लिए अंतिम संशोधन के दौरान पेश किया गया था, जबकि उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) पहले विनिर्माण मूल्य-वर्धित अनुमान लगाने का मुख्य स्रोत था।
- MCA-21 पर स्विच करने को इस दावे से उचित ठहराया गया था कि इसने फैक्ट्री परिसर से परे मूल्य संवर्धन का अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे तेजी से बढ़ते PCS को बेहतर तरीके से कैप्चर किया जा सका।

### नए अनुमानों का बचाव

- NSO ने अपने नए अनुमानों का बचाव करते हुए दावा किया कि उन्होंने अधिक व्यापक डेटाबेस और बेहतर अनुमान विधियों का उपयोग किया है जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित हैं।
- आलोचक इस बात को लेकर चिंतित रहे कि क्या एक बड़ा डेटासेट स्वाभाविक रूप से अधिक सटीक अनुमानों की ओर ले जाता है, क्योंकि सरकार ने एमसीए डेटा को स्वतंत्र सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया।

### अतिशयोक्ति के साक्ष्य

- 2012-13 से 2019-20 तक राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) और एसआई के आधार पर सकल मूल्य वर्धित (GVA) और सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) के बीच तुलना में महत्वपूर्ण विसंगतियां सामने आईं।
- GVA की औसत वार्षिक वृद्धि दर एनएस के अनुसार 6.2% थी, लेकिन एसआई के अनुसार केवल 3.2% थी, जो एनएस अनुमानों में व्यवस्थित रूप से अधिक आकलन का संकेत देती है।

### जीएसटी डेटा उपयोग के लिए सावधानी

- साक्ष्य जीडीपी अनुमान के लिए GST डेटा का उपयोग करने में सावधानी की आवश्यकता को उजागर करता है।
- यह कठोर परीक्षण के बिना असत्यापित डेटासेट और कार्यप्रणाली को जल्दबाजी में लागू करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करता है।
- NSO को विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन का अनुमान लगाने के लिए जीएसटी डेटासेट की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए पायलट अध्ययन करना चाहिए।

### निष्कर्ष और सिफारिशें

- हालांकि जीएसटी डेटा में इसकी व्यापकता के कारण GDP अनुमान को बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन इसकी पारदर्शिता की कमी जीडीपी अनुमानों को मान्य करने के लिए चुनौतियां पेश करती है।
- जीएसटी डेटा के आधार पर जीडीपी अनुमानों की वैधता स्थापित करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा व्यवस्थित विश्लेषण और क्रॉस-वैलिडेशन आवश्यक है।



- ➔ वैकल्पिक रूप से, एनएसओ विनिर्माण क्षेत्र में जीडीपी का अनुमान लगाने के लिए एसआई पर वापस लौटने पर विचार कर सकता है, क्योंकि यह अब अधिक समय पर और उपयोग के लिए उपलब्ध है।

**UPSC Mains PYQ: 2021**

**प्रश्न: वर्ष 2015 से पहले और वर्ष 2015 के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना पद्धति के बीच अंतर स्पष्ट करें।**



लेख में भारत में न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व पर चर्चा की गई है और न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की गई है, तथा पारदर्शी और जवाबदेह चयन प्रक्रिया की वकालत की गई है।

➔ यह न्यायपालिका की अखंडता और जनता के विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता पर जोर देता है।

## Judicial appointments and disappointments

Judges are the ultimate authority in the interpretation of the Constitution, and so must be learned in the law. But who will select the judges, and ascertain their qualifications and class character?

V. R. Krishna Iyer

On September 20, the Supreme Court asked the Attorney General for India why the names reiterated by the Supreme Court Collegium for appointment as judges were not yet cleared, as Collegium reiterates are binding on the Union government. Following the remark, the Union government processed the appointment of eight new High Court Chief Justices. In this article dated December 4, 2021, V. R. Krishna Iyer talks about the importance of upholding the judiciary's independence.

The Constitution of India operates in happy harmony with the instrumentalities of the executive and the legislature. But to be truly great, the judiciary exercising democratic power must enjoy independence of a high order. But independence could become dangerous and undemocratic unless there is a constitutional discipline with rules of good conduct and accountability; without these, the robes may prove arrogant.

It is in this context that Chief Justice S.H. Kapadia's observations, at an event at the Supreme Court of India on Independence Day, underlining the need for the government to balance judicial accountability with judicial independence, have to be reconciled with what Law Minister Salman Khurshid observed about judicial propriety. It is this reconciliation of the trinity of instrumentality in their functionalism that does justice to the Constitution. A great and grand chapter on judicial sublime behaviour to forbid the "robes" becoming unruly or rude and to remain ever sober is obligatory.

The Constitution has three instrumentalities – executive, legislative and judicative. The implementation of the state's laws and policies is the responsibility of the executive. The Cabinet headed by the Prime Minister at the Centre and the Cabinet led by the Chief Minister in the States, are its principal agencies. The rule of law governs the administration.

Parliament consisting of two Houses and legislatures at the State level make law. When the executive and the legislature do anything that is arbitrary, or contrary to the constitutional provisions, the judiciary has the power to correct them by issuing directions under Article 143. The Constitution lays down the fundamental rights, and if the States do not safeguard them, any citizen can approach the Supreme Court for the issue of a writ to defend his or her fundamental rights. Thus, among the three instrumentalities, the judiciary has pre-eminence. But the judiciary itself has to act according to the Constitution and work within the framework of the Constitution.

Felix Frankfurter pointed out thus: "Judges as persons, or courts as institutions, are entitled to no greater immunity from criticism than other persons or institutions. Just because the holders of judicial office are identified with the interests of justice they may forget their common human frailties and failibilities. There have sometimes been martinetts upon the bench as there also been pompous wielders of authority



ISTOCKPHOTO

who have used the paraphernalia of power in support of what they called their dignity. Therefore judges must be kept mindful of their limitations and of their ultimate public responsibility by a vigorous stream of criticism expressed with candour however blunt."

### Ultimate authority

Judges are the ultimate authority in the interpretation of the Constitution, and so must be learned in the law and in the cultural wealth of the world. They play a vital role in the working of the Constitution and the laws. But how judges are appointed is a matter of concern. Simply put, the President appoints them, but in this the President only carries out the Cabinet's decisions.

The Preamble to the Constitution lays down as the fundamentals of the paramount law that India shall be a socialist, secular democratic republic which shall enforce justice – social, economic and political – and ensure

liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and promote among them fraternity, ensuring the individual's dignity and the nation's unity and integrity.

### Need for clarity

But who will select the judges, and ascertain their qualifications and class character? Unless there is a clear statement of the principles of selection, the required character and conduct of judges in a democracy may fail since they will often belong to a class of the proprietariat, and the proletariat will have no voice in the governance: the proprietariat will remain the ruling class.

Winston Churchill made this position clear with respect to Britain thus: "The courts hold justly a high, and I think, unequalled pre-eminence in the respect of the world in criminal cases, and in civil cases between man and man, no doubt, they deserve and command the respect

and admiration of all classes of the community, but where class issues are involved, it is impossible to pretend that the courts command the same degree of general confidence. On the contrary, they do not, and a very large number of our population have been led to the opinion that they are, unconsciously, no doubt, biased."

We in India have under the Constitution the same weaknesses pointed out by Churchill, with the result that socialism and social justice remain a promise on paper. Then came a new creation called collegiums. The concept was brought in by a narrow majority of one in a 5-4 decision of the Supreme Court for the selection of judges. It was binding on the executive, the decisions of which in turn were bound to be implemented by the President.

Thus, today we have a curious creation with no backing under the Constitution, except a ruling of the Supreme Court, and that too based on a very thin majority in a single ruling. Today, the collegium on its own makes the selection. There is no structure to hear the public in the process of selection. No principle is laid down, no investigation is made, and a sort of anarchy prevails.

In a minimal sense, the selection of judges of the highest court is done in an unprincipled manner, without investigation or study of the class character by the members of the collegium. There has been criticism of the judges so selected, but the collegium is not answerable to anyone.

In these circumstances, the Union Law Minister has stated that the government proposes to change the collegium system and substitute it with a commission. But, how should the commission be constituted? To whom will it be answerable? What are the guiding principles to be followed by the Commission? These issues remain to be publicly discussed. A constitutional amendment, with a special chapter of the judiciary, is needed. Such an amendment can come about only through parliamentary action.

Surely a commission to select judges for the Supreme Court has to be of high standing. It must be of the highest order, of a status equal to that of the Prime Minister or a Supreme Court judge. The commission's chairman should be the Chief Justice of India.

In the process of selection, an investigation into the character, class bias, communal leanings and any other imputations that members of the public may make, may have to be investigated. This has to be done not by the police, which function under the government, but by an independent secret investigation agency functioning under the commission's control. These and other views expressed by outstanding critics may have to be considered.

The commission has to be totally independent and its ideology should be broadly in accord with the values of the Constitution. It should naturally uphold the sovereignty of the Constitution beyond pressures from political parties and powerful corporations, and be prepared to act without fear or favour, affection or ill-will. It should act independently – such should be its composition and operation. The commission should be immune to legal proceedings, civil and criminal. It should be removed only by a high tribunal consisting of the Chief Justice of India and the Chief Justice of all the High Courts sitting together and deciding on any charges publicly made. We, the people of India, should have a free expression in the commission's process.

V.R. Krishna Iyer, eminent jurist, is a former Judge of the Supreme Court of India.

संवैधानिक शक्तियों का सामंजस्य

- भारतीय संविधान कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के बीच सामंजस्यपूर्ण संचालन सुनिश्चित करता है।
- न्यायपालिका के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, इसमें उच्च स्तर की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- हालाँकि, सत्ता के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए इस स्वतंत्रता को संवैधानिक अनुशासन के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

### उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता को संतुलित करना

- मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया ने सरकार द्वारा न्यायिक जवाबदेही और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- न्यायिक मर्यादा बनाए रखने के लिए सरकार की तीनों शाखाओं के बीच परस्पर क्रिया को संवैधानिक सिद्धांतों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।

### तीनों साधनों की भूमिकाएँ

- कार्यपालिका कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट प्राथमिक एजेंसियों के रूप में कार्य करती है।
- संसद और राज्य विधानसभाओं से मिलकर बनी विधायिका कानून बनाती है।
- न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, जो कार्यकारी और विधायिका द्वारा मनमानी कार्रवाइयों को सही करती है।

### न्यायिक अधिकार और आलोचना

- न्यायाधीशों के पास संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार होता है और उन्हें कानून और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति एक चिंता का विषय बनी हुई है; जबकि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, यह कैबिनेट के निर्देश पर किया जाता है।
- वर्गीय पक्षपात को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विविध आवाज़ों का प्रतिनिधित्व हो, न्यायिक चयन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों में स्पष्टता आवश्यक है।

### कॉलेजियम प्रणाली का उदय

- न्यायिक चयन के लिए कॉलेजियम प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय में एक संकीर्ण बहुमत के फैसले से पेश किया गया था।
- यह प्रणाली संवैधानिक समर्थन के बिना संचालित होती है, जिससे न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी होती है।

### सुधार की आवश्यकता

- कॉलेजियम प्रणाली को आयोग से बदलने के केंद्रीय कानून मंत्री के प्रस्ताव ने इसकी संरचना और जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं।
- न्यायिक चयन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन आवश्यक है।

### न्यायिक चयन आयोग का प्रस्ताव

- एक नए आयोग में प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर उच्च प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जिसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश हों।
- न्यायिक उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्वाग्रहों की जांच सरकार से संबद्ध पुलिस के बजाय एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए।

### स्वतंत्रता और अखंडता सुनिश्चित करना



## Daily News Analysis

- प्रस्तावित आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और राजनीतिक संस्थाओं और निगमों के बाहरी दबावों का विरोध करना चाहिए।
- इसे कानूनी कार्यवाही से मुक्त रखा जाना चाहिए, और इसे केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश और सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों वाले उच्च न्यायाधिकरण के माध्यम से हटाया जाना संभव होना चाहिए।

### जनता की भागीदारी का महत्व

- आयोग की प्रक्रियाओं में जनता के इनपुट की अनुमति होनी चाहिए, जिससे न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
- इस तरह के सुधारों का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि यह जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे।

### UPSC Prelims PYQ : 2019

#### प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के संविधान में 44वें संशोधन ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे रखने वाला एक अनुच्छेद पेश किया।
  2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले भारतीय संविधान के 99वें संशोधन को रद्द कर दिया।
- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

## Temple In News : Tirupati Balaji Temple

तिरुपति लड्डू को लेकर बढ़ते विवाद के बीच, प्रसिद्ध भगवान बालाजी मंदिर को घी की आपूर्ति करने वाली कंपनी एआर डेयरी ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता का बचाव किया है।



तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में:

- तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में पहाड़ी शहर तिरुमाला में स्थित एक हिंदू मंदिर है।
- मंदिर समुद्र तल से 853 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और वेंकट पहाड़ी पर स्थित है, जो तिरुमाला पहाड़ियों की सप्तगिरि (सात पहाड़ियों) में से एक है।
- यह भगवान श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है, जो विष्णु के अवतार हैं।
- इसका उल्लेख गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण और कई अन्य पवित्र ग्रंथों में किया गया है।

### इतिहास:

- मंदिर की प्राचीन जड़ें पल्लव राजवंश से जुड़ी हैं, जिसका 9वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव था।
- इसके बाद, चोल राजवंश ने मंदिर के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- बाद में, विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान, मंदिर को महत्वपूर्ण योगदान और दान मिला, जिससे दक्षिण भारत के धार्मिक परिदृश्य में इसका स्थान मजबूत हुआ।
- मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण वह था जब प्रसिद्ध संत रामानुज ने 12वीं शताब्दी में मंदिर और इसके अनुष्ठानों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- दान और धन के मामले में यह दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है।
- मंदिर में एक लोकप्रिय प्रथा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए बाल और विभिन्न प्रकार की संपत्ति का दान करना।
- तिरुपति लड्डू: मंदिर में प्रसाद के रूप में दी जाने वाली प्रसिद्ध मिठाई, तिरुपति लड्डू को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त है।

### वास्तुकला:

- मंदिर का निर्माण द्रविड़ वास्तुकला में किया गया है और माना जाता है कि इसका निर्माण 300 ईस्वी से शुरू होने वाले समय की अवधि में हुआ है।
- गर्भगृह में तीन प्रवेश द्वार हैं - पहले को महाद्वारम कहा जाता है।
- प्रवेश द्वार के सामने 50 फीट का एक गोपुरम (प्रवेश द्वार) रखा गया है।
- इसमें दो परिक्रमा पथ हैं।
- मुख्य मंदिर में एक सोने की परत चढ़ी मीनार है जिसे आनंद निलयम कहा जाता है, और मीनार के अंदर एक मंदिर है जिसमें मुख्य देवता की प्रतिमा है।
- मंदिर के विशाल प्रांगण, स्तंभ और हॉल उत्कृष्ट मूर्तियों और डिजाइनों से सुसज्जित हैं जो हिंदू आध्यात्मिकता के सार को दर्शाते हैं।



# India needs a 'National Security Strategy'

The demand for a national security strategy is again under public discussion as the neighbourhood gets into a flux, old enemies muscle up, and new friends are yet to commit themselves. India's economic ambitions to be a \$4 trillion economy, is also likely to also face strong headwinds as the wars in Ukraine and Gaza continue, dragging down global growth. The economy is really the key to everything else. After all, everyone wants a slice of the economic pie, from the Ministry of Health to the Ministry of Defence. That means prioritisation within rather scarce resources, and that is the key to national security strategy making.

## Interpreting the term

For such an exercise, one has to first decide what comes under the umbrella term of 'national security'. The problem is it means different things to different states, at different times.

For the United States, it once centred around a 'union of our values and national interests'. That means you can stand up as the most powerful democracy, even while supporting a clutch of dictators for economic gain. After all, while Joe Biden's National Security Strategy (NSS) mentions 'values' 29 times, it is centred around the need to maintain America's leadership role. That means money. The U.S. NSS is the starting point for a host of other documents such as the Defence Department's National Defense Strategy, and thereafter, the 'Posture' document of each service. Then comes budgeting, where funds are sanctioned by Congress. Here is what else it is.

Across administrations, it is part of a power projection exercise, internally and externally. Externally, it is aimed to put the fear of god into such newly rising upstarts as China, and, internally, to project strength and determination to voters. Its public documents, therefore, showcase its capabilities, and sometimes exaggerate it. The United Kingdom which still sees itself as a global power, used an Integrated Review in 2021 that stressed working together with allies for a global role. It can hardly afford aircraft for its carriers, but it still helps to project oneself as a "European power with global interests". For President Emmanuel Macron of France, the 2022 review arose from the break out of the Ukraine war, and a restatement of French nuclear deterrent. It was a political document in a bid for European leadership. It did not quite work, but the point was that it was issued for a specific purpose. There are no two opinions on the fact that India needs an NSS, that will bring together diverse aspects such as defence, finance,



**Tara Kartha**

Director, (Research and Analysis) Centre for Land Warfare Studies (CLAWS), New Delhi

It needs to bring together diverse aspects such as defence and finance into a coherent whole; however, this is an exercise that needs to be conducted quietly

investments and climate change into one coherent whole, and then set a direction for the country. However this exercise needs to be done within the realm of top secrecy for some very good reasons. Consider that it will demand a clear statement of threat.

## Now, multi-alignment

Budget speeches make no reference at all to the 'enemy' outside or within. Indeed, they hardly even mention defence. While it is accepted that the protection of sovereignty and territorial integrity lies at the heart of national security, every Finance Minister is well aware that a strong economy is also aimed at an ability to retain sovereignty in international relations. Poor nations have to trail after the powerful ones, or form their own groupings. For India, that was once the Non-Aligned movement. That once 'core value' has been jettisoned given the need to defend itself against a belligerent eastern neighbour of highly unequal economic strength, even while not appearing to do so. Thus, it is "multialignment", which means making friends with whoever is capable and willing to provide a possible back up in a crisis, and perhaps defence technology. Hence the Quad (Australia, India, Japan and the U.S.), which discusses security bilaterally even while the grouping backs the freedom of the seas. On the other hand is BRICS, a China-led economic grouping together with Brazil and Russia, because you are not quite sure of putting all your eggs in one western basket. Besides, India's \$85 billion trade deficit with Beijing rather complicates things, given its frequent forays into and claims of Indian territory. Imagine how all of this would be described in a public national security document. No amount of good English can hide the fact that we cannot defend against China on our own, or that we have so little to do it with. Neither can we talk glibly about 'allies' like the U.K. does. We do not believe in alliances.

From threat prioritisation, the next level is the allocation of tasks to each service and the equipment that it needs to fulfil its mandate. True, defence budgeting is a relatively transparent exercise. However, a 'strategy' will need to decide which equipment or service one has to lean towards, and where it falls short. For instance, if the 'Indo-Pacific' is part of a strategy, then a hard exercise has to be on how to quickly upgrade your submarine- and ship-building capabilities. India's submarine strength is about a fourth of China's, while the picture is even worse in ship-building. Neither is the lag in the commissioning of warships something that you

would want to advertise. A clever drafter could get round the details, but then without a clear identification of where our priorities and weaknesses lie, it is hardly a worthwhile exercise. Transparency is for the strong and not for those struggling to catch up. That is also why Pakistan's defence budget is so opaque. A secret document on the other hand needs to highlight serious weaknesses, not just project 'can do' bravery. That is not strategy. That is hopeful optimism.

Now, consider what the central message needed for the voting public should be in an open document. The current trajectory of social media opinion demands a fair bit of chest thumping. Some of this is valid. After all, India is not prone to 'adventuring'. But when it went to the defence of another country, it delivered results and withdrew speedily unlike global hegemonies who got bogged down in places such as Afghanistan. These are values to be proud of. But neighbours would hardly appreciate one's tom-tomming this as a virtue – at least not in the current dispensation. Besides, a rapacious public wants more. It wants a declaration of might and more. This kind of bravado would have the Opposition on your neck. So, internally, it has little value for political gain. Externally, a written National Security document would hardly allow the dexterous foreign policy flexibility apparent from our careful balancing on the Russia-Ukraine and Gaza wars, for instance. Backing democracy strongly in a written NS document would then be an exercise in hypocrisy. The U.S. can be as hypocritical as it pleases. It is a world power. India is not.

## A full thread running through the economy

In sum, a national security document is an urgent need. It is not just about defence. Linked closely to it are priorities within the economy that will give a direction to industry, to financial institutions, and all the other tentacles that make up the lifeblood pulsing through the economy. That exercise is generally done piecemeal through various annual reports and surveys. The trick is to integrate it all together and set a direction for the country to reach where it wants to go, and fast. Therefore, the exercise is one best kept close to one's chest, even as directives are issued separately to ministries and others. The National Security Council Secretariat is more than up to the task. Similar exercises have been done before, though in a voluminous style so beloved of bureaucracy. Here is some advice: keep it simple, keep it short, and keep it specific. And, above all, keep it well under wraps. Your enemies would be dying to know its contents.

**GS Paper 02 : शासन – सरकारी नीतियाँ**

**PYQ : (UPSC CSE (M) GS-3 2023) :** आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में 'दिल और दिमाग' जीतना आबादी का विश्वास बहाल करने के लिए एक आवश्यक कदम है। जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के हिस्से के रूप में इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा करें। (150 words/10m)

**UPSC Mains Practice Question** वर्तमान भू-राजनीतिक चुनौतियों और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) के महत्व पर चर्चा करें। भारत को ऐसी रणनीति तैयार करते समय गोपनीयता, रक्षा प्राथमिकता और आर्थिक लचीलेपन के बीच किस तरह संतुलन बनाना चाहिए? (250 w /15 m)

**संदर्भ :**

- ▶ लेख में पड़ोसी देशों के साथ तनाव और वैश्विक संघर्षों सहित बढ़ती भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- ▶ यह रणनीतिक गोपनीयता बनाए रखते हुए रक्षा प्राथमिकताओं, आर्थिक लचीलेपन और कूटनीतिक लचीलेपन को संतुलित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

**राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की मांग**

- ▶ भारत के विकसित होते भू-राजनीतिक माहौल के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) की आवश्यकता फिर से सार्वजनिक चर्चा में आ गई है।
- ▶ चीन जैसे पुराने विरोधी मजबूत हो रहे हैं, जबकि अमेरिका जैसे नए गठबंधन अभी भी अनिश्चित हैं।
- ▶ भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाएँ, जैसे कि 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना, यूक्रेन और गाजा में चल रहे युद्धों से चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जो वैश्विक विकास को प्रभावित कर रही हैं।
- ▶ एक मजबूत अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य से लेकर रक्षा तक हर मंत्रालय आर्थिक संसाधनों के एक हिस्से पर निर्भर करता है।

**राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित करना**

- ▶ 'राष्ट्रीय सुरक्षा' शब्द समय और संबंधित राज्य के आधार पर अलग-अलग होता है।
- ▶ अमेरिका में, इसका मतलब कभी मूल्यों और राष्ट्रीय हितों का एक संघ था, जो आर्थिक लाभ के लिए आवश्यक होने पर तानाशाहों का समर्थन करने की अनुमति देता था।
- ▶ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) दस्तावेज़ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति प्रक्षेपण के उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं।
- ▶ यू.के. और फ्रांस जैसे देश आर्थिक या सैन्य सीमाओं के बावजूद अपनी वैश्विक भूमिकाओं पर जोर देने के लिए अपनी सुरक्षा रणनीतियों का उपयोग करते हैं।

### भारत की NSS की आवश्यकता

- ▶ भारत को एक सुसंगत NSS की आवश्यकता है जो रक्षा, वित्त, निवेश और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को एकीकृत करता है।
- ▶ NSS के निर्माण के लिए एक शीर्ष-गुप्त प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, यह देखते हुए कि इसके लिए चीन द्वारा उत्पन्न आर्थिक और सैन्य चुनौतियों जैसे खतरों की स्पष्ट पहचान की आवश्यकता होगी।
- ▶ सीमित संसाधनों के भीतर प्राथमिकता तय करने और रणनीतिक दिशाएँ निर्धारित करने के लिए इस तरह के अभ्यास की आवश्यकता है।

### भारत के दृष्टिकोण के रूप में बहु-संरक्षण

- ▶ भारत की "बहु-संरक्षण" की वर्तमान रणनीति में ऐसे देशों के साथ गठबंधन बनाना शामिल है जो संकट के समय रक्षा प्रौद्योगिकी और सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- ▶ क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यू.एस.) और ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) इस लचीले दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, क्योंकि भारत पश्चिमी शक्तियों और चीन दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करता है।
- ▶ चीन के साथ भारत का 85 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा, चीन के लगातार क्षेत्रीय घुसपैठ को देखते हुए, संबंधों को जटिल बनाता है।

### सार्वजनिक पारदर्शिता में चुनौतियाँ

- ▶ सार्वजनिक राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेज़, जैसे कि यू.एस. या यू.के. के दस्तावेज़, अक्सर राजनीतिक और कूटनीतिक उद्देश्यों के लिए ताकत को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं या उजागर करते हैं।
- ▶ भारत के मामले में, सार्वजनिक NSS में पारदर्शिता सैन्य और आर्थिक कमज़ोरियों को उजागर कर सकती है, विशेष रूप से जहाज निर्माण या पनडुब्बी क्षमताओं जैसे क्षेत्रों में, जहाँ भारत चीन से बहुत पीछे है।
- ▶ सार्वजनिक NSS विदेश नीति में भारत के लचीलेपन को भी कम कर सकता है, जैसा कि रूस-यूक्रेन और गाजा संघर्ष जैसे मुद्दों पर इसके सावधानीपूर्वक संतुलन में देखा जा सकता है।

### बजट और प्राथमिकताएँ

- ▶ राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक ताकत से निकटता से जुड़ी हुई है, जो बदले में रक्षा क्षमताओं को प्रभावित करती है।



## Daily News Analysis

- ▶ जबकि भारत का रक्षा बजट कुछ हद तक पारदर्शी है, NSS के लिए संसाधनों की स्पष्ट प्राथमिकता तय करना आवश्यक होगा, खासकर इंडो-पैसिफिक जैसे क्षेत्रों में, जहां भारत को अपनी नौसेना क्षमताओं को उन्नत करने की आवश्यकता है।
- ▶ पाकिस्तान का अपारदर्शी रक्षा बजट इस बात पर प्रकाश डालता है कि गोपनीयता कभी-कभी कितनी आवश्यक होती है, खासकर कमजोर देशों के लिए।

### आंतरिक और बाहरी संदेश

- ▶ एक सार्वजनिक NSS को सोशल मीडिया द्वारा संचालित राष्ट्रवाद की मांगों को भारत की सैन्य और आर्थिक सीमाओं की वास्तविकताओं के साथ संतुलित करने की आवश्यकता होगी।
- ▶ भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण अन्य देशों में देखी जाने वाली छाती पीटने से बचता है और परिणाम-उन्मुख कार्रवाई पर जोर देता है, जैसा कि विदेशी संघर्षों में इसके त्वरित, प्रभावी हस्तक्षेपों से प्रदर्शित होता है।
- ▶ सार्वजनिक NSS में किसी भी तरह की बहादुरी का प्रदर्शन राजनीतिक विरोधियों की आलोचना का सामना करेगा और भारत की कूटनीतिक लचीलेपन में बाधा डाल सकता है।

### एक केंद्रीय घटक के रूप में अर्थव्यवस्था

- ▶ एक NSS को आर्थिक लक्ष्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत करना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत अर्थव्यवस्था संप्रभुता और रक्षा क्षमताओं की नींव है।
- ▶ इस तरह के अभ्यास में उद्योगों, वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करने वाले अन्य क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित करना शामिल होगा।

### निष्कर्ष: एक विवेकपूर्ण लेकिन तत्काल आवश्यकता

- ▶ भारत को तत्काल एनएसएस की आवश्यकता है, लेकिन इसे गुप्त रखा जाना चाहिए ताकि विरोधियों के सामने इसकी कमज़ोरियाँ उजागर न हों।
- ▶ NSS संक्षिप्त, केंद्रित और आर्थिक तथा रक्षा प्राथमिकताओं से जुड़ा होना चाहिए, जिसमें आवश्यकतानुसार अलग-अलग मंत्रालयों को निर्देश जारी किए जाएँ।
- ▶ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय इस प्रयास का नेतृत्व कर सकता है, जिससे एक सुसंगत रणनीति सुनिश्चित हो सके जो भारत को उसके दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर ले जाए।